

टोल दर लागू झाल्यामुळे, लहान वाहनांसाठी टोल ५ ते १० रुपयांना कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिल २०२५ रोजी लागू केलेले टोल दर वाढ उलट होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, टोल दर गेल्या वर्षासारखेच राहू शकतात. २०२४ मध्ये टोल दर ७.५ टक्के आणि एप्रिल २०२५ पासून ५ टक्के वाढ करण्यात आली.

रबी सीजन की फसलों का एमएसपी बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया फैसला

सुशील मिश्र
 मुंबई, 1 अक्टूबर

केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए रबी सीजन की प्रमुख 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। गेहूँ, चना, जौ समेत 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की सिफारिशों के तहत की गई है। एमएसपी बढ़ाने के चलते केंद्र सरकार किसानों को 84263 करोड़ रुपये देगी

केंद्र सरकार ने ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उत्पादकों



को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी (कुसुम) के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर

के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूँ के लिए क्रमशः 250 रुपये प्रति क्विंटल, 225 रुपये प्रति क्विंटल, 170 रुपये प्रति क्विंटल और 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

विपणन सत्र 2026-27 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी में यह वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी निर्धारित करने की घोषणा के

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

मंजूर, 2 करोड़ किसानों को लाभ

रामवीर सिंह गुर्जर
 नई दिल्ली, 1 अक्टूबर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। जिस पर हजारों करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। जिससे काफी किसानों को लाभ होगा। साथ ही दलहन रकबा, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। दलहन मिशन से उन्नत बीजों, कटाई उपरतत बुनियादी ढांचे और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर कितना होगा खर्च

सरकार 6 साल तक चलने वाले दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर बड़ी राशि खर्च करने जा रही है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक क्रियान्वित होने वाले इस मिशन पर 11,440 करोड़ रुपये की बड़ी राशि की जाएगी। इस खर्च के माध्यम से यह मिशन अनुसंधान, बीज प्रणाली, क्षेत्र विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता को कवर करते हुए एक व्यापक रणनीति अपनाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता देश है। लेकिन घरेलू दलहन उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण दालों के आयात में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि हुई है।

मिशन से कैसे आएगी दलहन में आत्मनिर्भरता

इस मिशन के माध्यम से दलहन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कई स्तर पर काम किया जाएगा। जिनमें रकबा व उत्पादकता में वृद्धि के साथ प्रमाणित बीज वितरण शामिल है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दलहन किसानों को उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे, जो 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगे। दलहन बीजों की नवीनतम किस्मों तक किसानों



की पहुंच को मजबूत करने के लिए 88 लाख निःशुल्क बीज किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन का क्षेत्रफल 310 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही इससे उत्पादकता बढ़कर 1,130 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ इस मिशन से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मसूर की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करेगी।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से प्रसंस्करण उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से न केवल दलहन उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि इससे प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिलेगा। बाजारों और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए यह मिशन 1000 प्रसंस्करण इकाइयों सहित कटाई-पश्चात बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगा। जिससे फसल हानि कम होगी, मूल्य संवर्धन में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। इस मिशन से प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी। मिशन क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा और प्रत्येक क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप करेगा। इससे संसाधनों का अधिक प्रभावी आवंटन संभव होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी और दलहन उत्पादन के भौगोलिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय कर्मियों का महंगाई

भत्ता 3 % बढ़ा

रुचिका चित्रवंशी
 नई दिल्ली, 1 अक्टूबर

त्योहारों के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी।

वित्तिपति में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 1 जुलाई, 2025 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 55 प्रतिशत पर 3 प्रतिशत की वृद्धि के कर्मचारी बड़ी संख्या में है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा, '14 केंद्रीय विद्यालय उन जिलों में प्रस्तावित हैं जो थोड़े महत्वाकांक्षी हैं। 4 केंद्रीय विद्यालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में जबकि 5 केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं।'



57 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे

संकेत कौल

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 86,000 से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने बताया कि इन सभी 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्थापित करने के लिए अनुमानित कुल 5862.55 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह राशि वर्ष 2026-27 से शुरू होकर नौ साल की अवधि के दौरान खर्च की जाएगी। इसमें 2585.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (भवन निर्माण आदि पर खर्च) और 3277.03 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय (स्कूल चलाने का खर्च) शामिल है। इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 20 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जिलों में खुलेंगे जहां अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है लेकिन वहां केंद्र सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा, '14 केंद्रीय विद्यालय उन जिलों में प्रस्तावित हैं जो थोड़े महत्वाकांक्षी हैं। 4 केंद्रीय विद्यालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में जबकि 5 केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं।'

विविध समाचार

मंत्रिमंडल ने जैव-चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम के तीसरे चरण को दी मंजूरी

सरकार ने बुधवार को जैव-चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम (बीआरसीपी) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य 2,000 से अधिक विद्यार्थियों और 'पोस्ट-डॉक्टरल फेलो' को प्रशिक्षित करना, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में मदद करना है।

प्रधानमंत्री अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बीआरसीपी के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट, ब्रिटेन द्वारा 'इंडिया अलायंस' के माध्यम से 2025-26 से शुरू कर अगले छह वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जायेगा। 'पोस्ट-डॉक्टरल फेलो' वह व्यक्ति होता है जो पीएचडी पूरी करने के बाद अनुसंधान जारी रखता है, जिससे उसे अपने शोध क्षेत्र में पेशेवर कौशल विकसित करने और कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग का योगदान 1,000 करोड़ रुपये होगा तथा वेलकम ट्रस्ट, ब्रिटेन 500 करोड़ रुपये देगा।विश्व स्तरीय जैव-चिकित्सा अनुसंधान के लिए बीआरसीपी की शुरुआत 2008-09 में हुई थी। इसके बाद, चरण दो को 2018-19 में लागू किया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'अपेक्षित परिणामों में दो हजार से अधिक विद्यार्थियों और 'पोस्ट डॉक्टरल फेलो' को प्रशिक्षित करना, उच्च-प्रभावी प्रकाशन तैयार करना, पेटेंट योग्य खोजों को सक्षम बनाना, महिलाओं को मिलने वाले समर्थन में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि, 25-30 प्रतिशत सहयोगात्मक कार्यक्रमों को 'टीआरएल4' और उससे ऊपर के स्तर तक पहुंचाना शामिल है।' *भाषा*

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth Q&As with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Business Standard
Insight Out

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

पत्र सं. WB-74 W-O/Works/ NIT

दिनांक 30.09.2025

मंडल रेल प्रबंधक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.: 1 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26: 112of2025-26. **कार्य का नाम व स्थान:** Provision of new high-level PF 4/5, Extension of existing FOB from PF 2/3 to new PF 4/5 at Barmer station & Raising of PF No.2 from medium level to high level with O3 - seater benches water booths at Marwar Kori, Malwara & Kavas stations in the jurisdiction of Sr. DEN/West. **अनुमानित लागत रुपये:** 9,73,96,410.02. **बयाने की राशी रुपये:** 6,37,000/-.

क्र.सं.: 2 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26: 113of2025-26. **कार्य का नाम व स्थान:** Provision of W Metal Beam Crash Barrier (22000 m) in the section of SSE / PW / Barmer under ADEN/Barmer of Jodhpur Division. **अनुमानित लागत रुपये:** 8,04,69,078.60. **बयाने की राशी रुपये:** 5,52,400/-.

क्र.सं.: 3 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26: 114of2025-26. **कार्य का नाम व स्थान:** MISCELLANEOUS TRACK WORK IN THE JURISDICTION OF ADEN/BME OF JODHPUR DIVISION. **अनुमानित लागत रुपये:** 1,52,03,935.65. **बयाने की राशी रुपये:** 2,26,000/-.

क्र.सं.: 4 ई-निविदा सूचना सं. 2025-26: 115of2025-26. **कार्य का नाम व स्थान:** Various activities in C/W Through Ballast Recoupment (TBR) 12113 Km. From 834.19 Km. To Km.955.32 on Barmer-Munabao section under ADEN/Barmer of Jodhpur Division. **अनुमानित लागत रुपये:** 11,65,77,613.52. **बयाने की राशी रुपये:** 7,32,900/-.

निविदा सूचना संख्या 112of2025-26, 113of2025-26, 114of2025-26 एवं 115of2025-26 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 27.10.2025 को 15.00 बजे तक है वेबसाइट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है www.ireps.gov.in

1267-AR/25

🇮🇳 📶 📡 NWRRailways 📡 NWRRailways... पर फॉलो करें

BAJAJ FINANCE LIMITED

FINSEV

Registered Office: Bajaj Finance Limited, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune – 411014

Branch Office: Bajaj Finserv, Prestige Towers , 5th floor , Residency Road , Bangalore 560025

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of **Bajaj Finance Limited (BFL)**, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under Sec.13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand by **registered post ("Notice")** calling upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned hereunder to repay the amount mentioned in the notice U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers/Mortgagors/Guarantors named below having failed to repay the said amount, notice is hereby given to the Borrowers/Mortgagors/Guarantors and public in general that the undersigned has taken **Physical Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under Sec.13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealing with this property will be subject to the charge of the Bajaj Finance Limited, for the amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Loan Account No./Name of the Borrower(s) Mortgagor(s) Guarantor(s)	Description of Secured Immovable Property	Date of Notice U/s.13(2) and U/s.13 (2) Notice Amount and Date of Possession
404FSLB6483285 & H404ECM0530139 Adnan Pasha (Borrower) AT: - No 138 2nd Cross, Beerappa Garden, Chamundinagar, RT Nagar, Bangalore-560032. Waheeda Kanum (Co-borrower) AT: - No 516 Beerappa Garden, Chamundinagar, RT Nagar, Bangalore-560032. A M Car Garage (Co-borrower) (Through its proprietor/Authorised signatory/ Managing Director) AT: - No 111, 1st Cross, External Excise, Layout, Bhooopandra, Bengaluru-560094	All the piece and parcel of the non-agricultural property described as: Property bearing BBMP No. 12 And 13 (Old No.9 and 10 And Earlier Bearing No. 8 And 9), situated at N.H.K Road Kalasipalya Main Road (Earlier Called as Laskar Lake) Bangalore-560002 Corporation Ward No. 47, measuring East to West 16 feet and North to South 26 ft 6 inches totally measuring 424 sq. ft, comprising of Ground, First and Second Floor Non-residential property having PID No. 47-46-12 And 47-46-13, East: Church Property, West: Nawab Hyder Ali Khan Road (Kalasipalya Main Road), North: Private Property (earlier Audugodi Chinnappa House), South: Private Property (earlier Azeen Bhai Shop).	17/02/2024 Rs.74,39,075/- (Rupees Seventy-Four Lakh Thirty-Nine Thousand and Seventy-Five Only) as on 07/02/24 Possession Date 30/09/2025

Date: 03.10.2025

Place: BANGALORE

Sd/- Authorized Officer, Bajaj Finance Limited

PUBLIC NOTICE

Public are informed that, my client **Mr. PRAKASH. K** Son of Mr. Karthikeyan Aged about 36 years, Residing at: No.103/5, 1st Floor 14th Cross, Opposite to Impact Destiny Apartment Nisarga Colony, Vijaya Bank Colony Extension Horamavu, Bangalore – 560 043 PAN : BIAPP5127J Aadhaar No.3892 0920 3870 will be going to purchase the property bearing Site No.29, (Eastern Portion in Southern Portion of Site No.29), Katha No.178/92/1, BBMP Katha EPID No.6153859387, situated at: HORAMAVU Village, K. R. Puram Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore, Now under the limits of BRUHATH BANGALORE MAHANAGARA PALIKE, Bangalore, measuring East to West 25 feet and North to South 30+35/2 feet in all measuring 812.5 Square feet from its previous owner **MR.KMASHWINKUMAR@MDILEEPKUMAR**. Also, public are informed that Seller has changed his name from **MR. M DILEEP KUMAR** to **MR. K M ASHWIN KUMAR**, Also state that Mr. K M ASHWINKUMAR @ M DILEEP KUMAR has taken Paper publication and Executed Affidavit on **25.08.2009**.

Whereas, Mr. K M ASHWINKUMAR @ M DILEEP KUMAR has acquired said property through deed from its previous owner Mrs. K Jayalakshmi on 19.12.2007 vide document no.3554/2007-08. Any person's or if any one having any claim over the said property or any other claims by any person/s, Nationalized banks, MNC Banks, private Banks, Co-operative banks any financial institutions Governed by the RBI rules may lodge their objections in writing within 07 days from this day to the under mentioned Advocate.

KBS Associates
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
OFFICE No 641, 29th Main, 12th Cross, J P Nagar 1st Phase, Bangalore – 560078
Email – kbsassociatesbangalore@yahoo.com
Mobile: 9008965571

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: U31108PN2013PLC146157

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name "Adisoft Technologies Private Limited" on February 04, 2013, under the provisions of the Companies Act, 2013, with the Registrar of Companies, bearing CIN: U31108PN2013PTC146157. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extraordinary General Meeting held on September 11, 2025. Consequently, the name of our Company was changed from "Adisoft Technologies Private Limited" to "Adisoft Technologies Limited", and a fresh certificate of incorporation reflecting the conversion to a public company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on September 17, 2025. Our Company's Corporate Identity Number is U31108PN2013PLC146157, please refer to chapter titled **"History and Corporate Structure"** beginning on page 138 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: Prathamesh Complex & Trading Plot No. PAP-BG-102, 103, 104 & 105, 1st and 2nd Floor, MIDC Chinchwad Industrial Area, Bhosari I.E., Pune - 411026, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 8208781102, **E-mail:** cs@adisoft.co.in; **Website:** www.adisoft.co.in
Contact Person: Vaibhav Nandkumar Salunke, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: AJAY CHANDRASHEKHAR PRABHU AND PREETI AJAY PRABHU

“THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (“NSE EMERGE”).

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 43,08,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED (“OUR COMPANY” OR “THE ISSUER”) AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ (●) LAKHS (“PUBLIC ISSUE”) OUT OF WHICH (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ (●) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (●) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.40% AND (●)% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITION OF (●) (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITION OF (●) (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND HINDI EDITION OF (●), REGIONAL NEWSPAPER (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF PUNE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF NSE (“NSE EMERGE”) FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding ten working days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of one working day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding ten working days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (“SCRR”) read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”, the “QIB Portion”), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (“Anchor Investor Portion”), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and under-subscription in either of these sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Bidders using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see **"Issue Procedure"** beginning on page 259 of this Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 247(2) of the SEBI ICDR Regulations, to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares of face value of ₹ 10 each pursuant to the Issue and the Draft Red Herring Prospectus dated September 30, 2025 has been filed with the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited (“NSE Emerge”) on September 30, 2025. The Draft Red Herring Prospectus filed with SME Platform of NSE (“NSE Emerge”) shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of NSE at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents/sme_offer, on the website of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company www.adisoft.co.in. Our Company invites the public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with SME Platform of NSE (“NSE Emerge”) with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM in relation to the Issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with SME Platform of NSE (“NSE Emerge”).

Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares to be issued have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to **"Risk Factors"** beginning on page 24 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the SME Platform of NSE (“NSE Emerge”). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see “Capital Structure” beginning on page 66 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see **"History and Corporate Structure"** beginning on page 138 of the Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the Issue has handled 69 Public Issues in the past three years, out of which 3 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	67	3 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
Hem Securities	KFINTeCH EXPERIENCE TRANSFORMATION
HEM SECURITIES LIMITED Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India Tel. No.: +91- 22- 49060000; Email: ib@hemsecurities.com Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com ; Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Ajay Jain SEBI Regn. No. INM000010981	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Address: Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana Telephone: +9140-67162222; Email: adisoft ipo@kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com ; Website: https://www.kfintech.com/ Contact Person: M. Murali Krishna, Senior VP SEBI Registration Number: INR000000221 ; CIN: L72400MH2017PLC444072
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER	
Vaibhav Nandkumar Salunke ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED Registered Office: Prathamesh Complex & Trading Plot No. PAP-BG-102, 103, 104 & 105, 1st and 2nd Floor, MIDC Chinchwad Industrial Area, Bhosari I.E., Pune - 411026, Maharashtra, India E-mail: cs@adisoft.co.in , Tel.: +91 8208781102, Website: www.adisoft.co.in	

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

Place: Pune, Maharashtra
Date: October 01, 2025

On behalf of the Board of Directors
Adisoft Technologies Limited
Sd/-
Vaibhav Nandkumar Salunke
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Adisoft Technologies Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on September 30, 2025. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents/sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company www.adisoft.co.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled **"Risk Factors"** beginning on page 24 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.